

श्री अरविन्द कुमार चौधरी, सचिव, ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में संपन्न दिनांक- 05.03.2016 (मंगलवार) को हुई वरीय पदाधिकारियों के साथ साप्ताहिक बैठक की कार्यवाही के सामान्य बिन्दु:-

1. इंदिरा आवास योजना

- वित्तीय वर्ष- 2015-16 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप जिलों में शतप्रतिशत आवास स्वीकृत कराने हेतु लगातार अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया । 2,32,800 लाभार्थियों को आवास सॉफ्ट पर स्वीकृति दिये जाने की जानकारी प्रदान की गई । यह बताया गया कि वित्तीय वर्ष- 2015-16 में आवास सॉफ्ट पर स्वीकृति दिये जाने की प्रक्रिया को बंद कर दिया गया है ।
- अभीतक 2,21,500 लाभार्थियों के FTO जनरेट करने का जानकारी प्रदान की गई एवं कुल 1,71,724 लाभार्थियों का Credit Confirmation आवास सॉफ्ट पर प्रदर्शित होने की जानकारी दी गई । PMFS पर लंबित FTOS के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया ।
- आवास सॉफ्ट पर 3,19,000 आवास पूर्ण होने की जानकारी दी गई जो कि पिछले सप्ताह 2,73,000 था ।
- आई0टी0 निदेशक श्री सरोज कुमार को यह निदेश दिया गया कि प्रत्येक सप्ताह Mobile Monitoring system (SAAS) का अनुश्रवण कर प्रतिवेदन उपस्थापित किया जाय ।

(अनुपालन:- विनोद कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी एवं श्री सरोज कुमार, आई0टी0 निदेशक)

2. मनरेगा

- अबतक 7.26 करोड़ मानव दिवस सृजित करने की जानकारी प्रदान की गई, जो कि पिछले सप्ताह 6.54 करोड़ मानव दिवस था ।
- कुल निर्गत 2,18,000 ई-मस्टर रॉल को जिसे एम0आई0एस0 पर इंट्री कराये जाने का निर्देश दिया गया, में से इस सप्ताह 90,000 अवशेष रह गया है । इन सभी ई-मस्टर रॉल को इंट्री कराये जाने का निदेश दिया गया ।
- अनुमोदित श्रम बजट के अनुरूप भारत सरकार द्वारा निर्देशित फोकस एरिया के तहत सभी जिलों को योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु पत्र दिये जाने का निदेश दिया गया ।
- सभी जिलों से पूर्ण अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने की जानकारी प्रदान की गई । भारत सरकार को प्रस्ताव भेजे जाने की जानकारी प्रदान की गई ।
- सभी SQM को जिला आवंटित करते हुए मनरेगा के विभिन्न मापदंडों पर अनुश्रवण कर वांछित प्रगति प्राप्त करने हेतु एक कार्य योजना बनाये जाने का निदेश दिया गया था । इस संबंध में पुनः निदेश दिया गया कि जिलों में भ्रमण हेतु SQM दल का निर्माण कर लिया जाय एवं तत्संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाय ।
- DTRT एवं BTRT के चयन से संबंधित गाईड-लाईन सभी जिलों को भेजे जाने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालन: सी0पी0 खंडूजा, निदेशक सामाजिक वानिकी संयोज कुमार सिंह, उप सचिव एवं मनोज कुमार सिन्हा, वित्त नियंत्रक)

3. Court Cases

- लंबित कोर्ट केस (MJC/CWJC) से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन की समीक्षा की गई, बताया गया कि IWDMS पर CWJC के 91 मामले लंबित रह गये हैं, जो कि पिछले सप्ताह 103 थे । इसके इंट्री को

अद्यतन कराते रहने का पुनः निदेश दिया गया साथ ही MJC के लंबित 7 (5+2) मामलों में कारण पृच्छा दायर किये जाने का निदेश दिया गया ।

- SGRY खाद्यान घोटले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गठित आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों को सभी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराये जाने के संबंध में पुनः Follow up करने का निदेश दिया गया । बताया गया कि आयोग के सदस्यों के सेवा शर्त से संबंधित कार्रवाई पूर्ण हो गई है। यह भी जानकारी दी गई कि आयोग को भवन उपलब्ध कराने हेतु संबंधित विभाग के द्वारा आदेश निर्गत किया गया है । इस बिन्दु पर लगातार Follow up करने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालन -संजय कुमार सिंह, उप सचिव)

4. IWDMS/e-office

- विभाग में e-office लागू कराने हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया एवं bihar.gov.in पर विभागीय पदाधिकारियों/कर्मियों का ई-मेल निर्माण हेतु पुनः पत्र दिये जाने का निदेश दिया । आई0टी0 मैनेजर श्री सुनील कुमार को यह निदेश दिया गया कि विशेष सचिव को इस संबंधित हुई अद्यतन प्रगति से अवगत करायेगें एवं इससे संबंधित तीन प्रपत्रों को तैयार कर आई0टी0 विभाग को भेजेगें ।

(अनुपालन - सरोज कुमार, IT Director एवं सुनील कुमार, आई0टी0 मैनेजर)

5. विधान सभा/विधान मंडल से संबंधित प्रश्न

- विधान सभा के सत्र समाप्त होने की जानकारी दी गई एवं यह बताया गया कि सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिये गये हैं ।
- विभाग द्वारा दिये गये आश्वासन/ध्यानाकर्षण की सूची अगली बैठक में उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया । (अनुपालन - प्रमोद कुमार बिहारी, विशेष सचिव एवं महेन्द्र भगत, उप सचिव एवं जवाहर कामति, प्रशाखा पदाधिकारी)

6. ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) एवं IPPE II

- IPPE II के तहत प्रशिक्षण एवं आयोजना हेतु जिलों को आवंटित किये गये राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र के संबंध में यह जानकारी दी गई कि मुजफ्फरपुर एवं गया जिले से उपयोगिता प्रमाण पत्र अप्राप्त है । दोनों जिलों से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने का निदेश दिया गया ।
- IPPE II की डाटा इंटी समाप्त होने के उपरांत GPDP के सर्वेक्षित प्रपत्रों F एवं G की डाटा इंटी कराने हेतु जिलों के साथ अनुश्रवण कर इसमें भी प्रगति लाने हेतु निदेश दिया गया । निदेश दिया गया कि इसे संबंध में सभी उप विकास आयुक्तों के साथ एक भी0सी भी आयोजित किया जाय ।

(अनुपालन:- कुमारी सीमा, विशेष कार्य पदाधिकारी, शुभेन्द्र सान्याल, UNDP Consultant एवं सरोज कुमार, IT Director)

7. विभागीय कार्रवाई एवं आरोप

- 29 लंबित विभागीय कार्रवाई में से 16 के निष्पादन की जानकारी दी गई शेष लंबित 13 विभागीय कार्रवाई को निष्पादित करने हेतु अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया । निदेश दिया गया कि इस माह में सभी लंबित कार्रवाइयों को पुरा कर लिया जाय ।

(अनुपालन -चेत नारायण राय, विशेष कार्य पदाधिकारी)

8. BISPS

- इसके अंतर्गत की जाने वाली नियुक्तियों के संबंध में जानकारी दी गई कि रोस्टर सम्पुष्ट करने हेतु संचिका प्रशाखा 01 को भेजी गई है। रोस्टर सम्पुष्ट होने के पश्चात विज्ञापन प्रकाशित कर दिया जायेगा।

(अनुपालन - सी0पी0 खंडूजा, निदेशक सामाजिक वानिकी एवं अभ्येन्द्र मोहन सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी)


9. AG Reports/PAC Paras

- जिलों में लंबित AC/DC विपत्रों के समायोजन तथा लंबित UC की समीक्षा करते हुए उसका निष्पादन कराने का निदेश दिया गया।
- CAG/PAC के लंबित कंडिकाओं के अनुपालन हेतु विशेष रूप से वृहस्पतिवार अप0 03.00 बजे से विशेष सचिव के अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक कराने का निदेश दिया गया तथा इस बैठक में सभी संबंधित पदाधिकारी अद्यतन प्रतिवेदन के साथ उपस्थित होंगे।

10. जन शिकायत

- मुख्यमंत्री जनता दरवार से एवं विभाग में अन्य स्रोतों से प्राप्त शिकायतों के निष्पादन से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया।


(अनुपालन- कुमारी सीमा, विशेष कार्य पदाधिकारी)


(अरविन्द कुमार चौधरी)

सचिव

जापांक 268271 पटना दिनांक 06-04-2016

प्रतिलिपि:- सभी प्रभारी पदाधिकारी/वरीय पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सचिव 6/4/2016